न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी के सामने

सनी चुघ और अन्य --- अपीलकर्ता

बनाम

दर्शन लाल और अन्य -प्रतिवादी

1979 के आदेश क्रमांक 485 से प्रथम अपील

17 जनवरी 1985

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV) - धारा 110-बी - मोटर दुर्घटना के कारण एक युवा गृहिणी की मृत्यु - दावा याचिका दायर की गई - द्वारा। पति और नाबालिग बच्चे - ऐसे मामलों में मुआवजे की मात्रा - कैसे निर्धारित की जाए - अनुदान/मुआवजा देने के सिद्धांत - बताए गए।

यह माना जाता है कि अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि गृहिणी द्वारा घर के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, भले ही मुफ्त में प्रदान की गई हों, वास्तव में एक मौद्रिक मूल्य है जिसके संबंध में मुआवजा देय है, विशेष रूप से ऐसी सेवाओं के लाभार्थियों को जिसमें पति भी शामिल है। और बच्चे. इस तरह का मुआवजा पति को उसकी पत्नी की मृत्यु पर और बच्चों को उनकी मां के संबंध में आर्थिक हानि के विभिन्न मदों के तहत दिया जा सकता है। इसमें पत्नी के योगदान की हानि भी शामिल है। उसकी कमाई से घर, पत्नी के बजाय गृहस्वामी या नौकर द्वारा घर चलाने से होने वाले अतिरिक्त खर्च या होने की संभावना, बच्चों के लिए कपड़े पत्नी से बनवाने के बजाय खरीदने का खर्च; और इसी तरह पति के अपने कपड़े उसकी पत्नी के अलावा कहीं और मरम्मत या सिलवाना और इससे पति को मिलने वाली सुरक्षा के उस तत्व का नुकसान हो जाता है, जहां उसका रोजगार असुरक्षित था या उसका स्वास्थ्य खराब था और जहां पत्नी बाहर जाकर काम कर सकती थी। जीविका। यह भी ध्यान में रखना उचित है कि गृहिणी की कोई सेवानिवृत्ति की आयु नहीं होती है और वह तब तक घर में काम करती रहती है जब तक वह शारीरिक रूप से ऐसा करने में सक्षम होती है। इस आलोक में विचार करें तो यह होना ही है। यह मान लिया गया कि मृतिका अपनी उम्र के कारण आने वाले कई वर्षों तक अपने पति और बच्चों को ऐसी सेवाएं प्रदान करती रही होगी और यह तथ्य मोटर की धारा 110-बी के तहत दावेदारों को देय मुआवजे की मात्रा पर भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। वाहन अधिनियम, 1939।

(अनुच्छेद 3 और 4)

श्री आर.के. नेहरू की अदालत, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, करनाल के दिनांक 19 मई, 1979 को रुपये का पुरस्कार पारित करने के आदेश से पहली अपील। राज कुमार दावेदार के पक्ष में और दावा याचिका में उत्तरदाताओं के खिलाफ दावा मुआवजे के रूप में 1500/- रु. राज कुमार बनाम सुरजीत सिंह नंबर 30/75 आनुपातिक लागत के साथ और रुपये का पुरस्कार भी। दावा याचिका सन्नी चुग बनाम दर्शन लाल एवं अन्य क्रमांक 26/75 में आनुपातिक लागत के साथ दावेदारों के पक्ष में एवं प्रतिवादियों के विरूद्ध 14400/- रू. ये पुरस्कार बीमा कंपनी प्रतिवादी द्वारा दोनों दावा याचिकाओं में संतुष्ट होंगे। आगे निर्देश दिया गया कि मुआवजा राशि रु. दावा याचिका संख्या 26/75 में दिए गए 14,400/- रुपये को दावेदारों द्वारा समान शेयरों में साझा किया जाएगा। आगे यह निर्देश दिया गया कि यदि ऊपर उल्लिखित दो याचिकाओं में दावेदारों को दिया गया उपरोक्त दावा मुआवजा इस पुरस्कार के पारित होने के एक महीने के भीतर प्रतिवादी बीमा कंपनी द्वारा उन्हें भुगतान किया जाता है, तो उपरोक्त राशि पर कोई ब्याज का दावा नहीं किया जाएगा। दावेदार अन्यथा दावेदार उपरोक्त दावा राशि पर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे। उनके संबंधित दावा याचिका दायर करने के दिन से लेकर वसूली की तारीख तक।

अपीलकर्ताओं के लिए वकील डी. एस. बाली।

वी. पी. गांधी, वकील, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के लिए हरभगवान सिंह, ए.जी., हरियाणा और बी.एस. पवार, ए.ए.जी., हरियाणा।

सनी चुघ और अन्य बनाम दर्शन लाल और अन्य (जस्टिस एस.एस. सोढ़ी)

निर्णय

जस्टिस एस.एस. सोढ़ी

1) जब हरियाणा रोडवेज की बस एचआरई-1916, जिसमें वे यात्रा कर रहे थे, विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक एचआरके-5335 के साथ दुर्घटना में पलट गई, तो कई यात्री घायल हो गए और एक की मौत हो गई, अर्थात्, उर्मिला चुघ। यह 12 नवंबर 1974 को करनाल बाईपास पर हुआ था। ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष था कि यहां लापरवाही पूरी तरह से ट्रक-चालक की थी। रुपये की राशि. दावेदारों को मुआवजे के रूप में 14,400 रुपये दिए गए वे मृतक उर्मिला चुघ के पति और दो नाबालिग बच्चे थे।

2) अब अपील में दावा बढ़े हुए मुआवजे के लिए है।

3) मृत्यु के समय उर्मिला चुघ की आयु 29 वर्ष थी। वह एक कुशल शिक्षिका थी और अपनी शादी के बाद से ही पढ़ा रही थी और इस बात के सबूत हैं कि वह उसके बाद ट्यूशन ले रही थी और स्रोत से उसकी कमाई लगभग रु. 450 प्रति माह. हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने इसे स्वीकार नहीं किया। किसी भी दर पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि मृतक एक योग्य शिक्षक था और इस प्रकार काम करने और कमाने में सक्षम था। इसके अलावा, अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक गृहिणी घर के लिए जो सेवाएँ प्रदान करती है, भले ही वह नि:शुल्क प्रदान की गई हो, उसका वास्तव में एक मौद्रिक मूल्य होता है जिसके संबंध में मुआवजा देय होता है, विशेष रूप से ऐसी सेवाओं के लाभार्थियों को जिसमें शामिल होगा पति और बच्चे. केम्प एंड केम्प में, क्वांटम ऑफ डैमेज, खंड-1 में, पत्नी की मृत्यु पर पति को होने वाली आर्थिक हानि के विभिन्न शीर्षकों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें अपनी कमाई से घर में पत्नी के योगदान की हानि भी शामिल है; पत्नी के बजाय गृहस्वामी या नौकर द्वारा घर चलाने पर होने वाला अतिरिक्त खर्च या होने की संभावना; बच्चों के लिए कपड़े पत्नी से बनवाने के बजाय खरीदने का खर्च; और इसी तरह अपने कपड़े अपनी पत्नी के अलावा कहीं और मरम्मत या सिलवाना, और पति को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के उस तत्व का नुकसान, जहां उसका रोजगार असुरक्षित था या उसका स्वास्थ्य खराब था और जहां पत्नी बाहर जाकर आजीविका के लिए काम कर सकती थी।

4) यह भी ध्यान में रखना उचित है कि गृहिणी के लिए सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं है। वह तब तक घर में काम करती है जब तक वह ऐसा करने में शारीरिक रूप से सक्षम है। इस प्रकाश में विचार करने पर, यह माना जा सकता है कि मृतक आने वाले कई वर्षों तक अपने पति और बच्चों को ऐसी सेवाएं प्रदान करता रहेगा। उसकी कम उम्र और यहां के दावेदारों की उम्र भी उन्हें देय मुआवजे की मात्रा पर निर्भर करेगी।

5) दावेदारों और मृतक की परिस्थितियों पर समग्रता से विचार करते हुए, ऊपर बताए गए कारकों के प्रकाश में, कोई तरीका या संदेह नहीं हो सकता है कि प्रदान की गई राशि पूरी तरह से

अपर्याप्त थी। तदनुसार, उन्हें देय मुआवजा बढ़ाकर रु. 50,000 रुपये की राशि वे आवेदन की तारीख से दी गई राशि के भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित पाने के हकदार होंगे। प्रदान की गई राशि में से रु. प्रत्येक मृतक के नाबालिग बच्चों को 15,000 रुपये और शेष राशि उसके पति को देय होगी। छोटे दावेदारों को देय राशि का भुगतान उन्हें इस तरह से किया जाएगा जैसा ट्रिब्यूनल उनके सर्वोत्तम हित में समझे।

6) प्रतिवादी ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी दिए गए मुआवजे के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

7) तद्नुसार यह अपील लागत सहित स्वीकार की जाती है। परामर्श शुल्क रु. 500।

एच.एस.बी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वहअपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा